मेहनत और नवाचार से राजस्व क्रांति के सूत्रधार

पर्वतजन ब्यूरो

उत्तराखंड के खनन एवं भूतत्व विभाग में एक नाम ऐसा है जो न केवल विभागीय इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो चुका है, बल्कि राज्य की आर्थिक प्रगति का पर्याय बन गया है। वह नाम है राजपाल लेघा, जो वर्तमान में विभाग के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे राजपाल लेघा ने अपनी मेहनत, इमानदारी और दूरदर्शी नेतृत्व से उत्तराखंड के खनन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनके नेतृत्व में विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 1100 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जो राज्य के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक है। यह उपलब्धि न केवल उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और अवैध खनन पर लगाम लगाने में भी मील का पत्थर साबित हो रही है। राजपाल लेघा की नीतियां अब अन्य राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर द्वारा अपनाई जा रही हैं, जो उनके योगदान की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता का प्रमाण हैं।

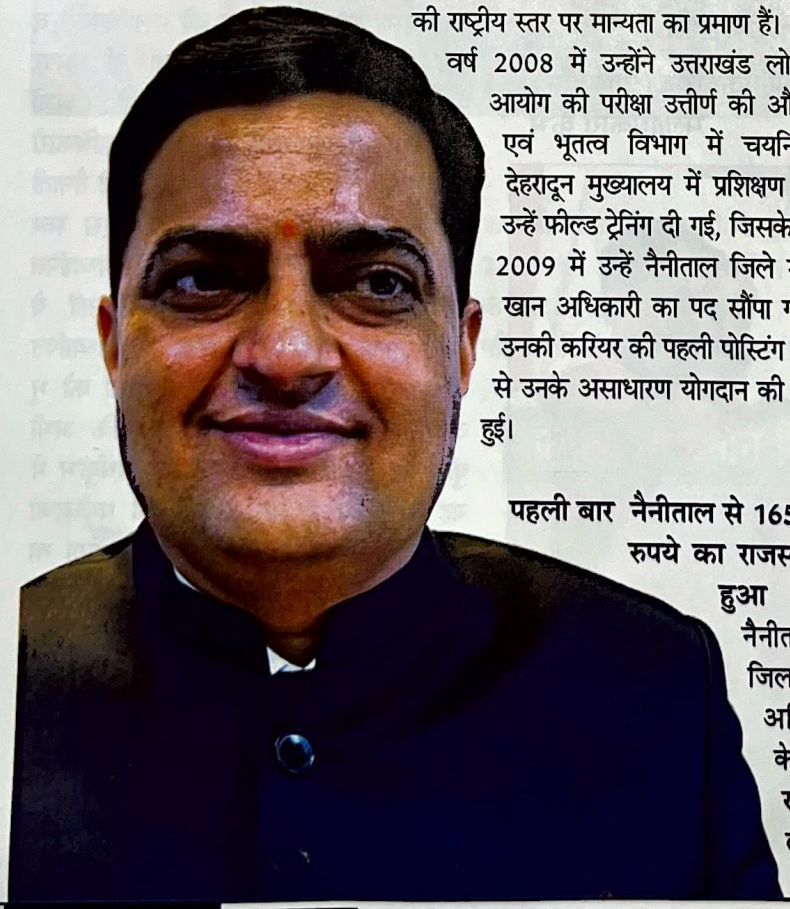

वर्ष 2008 में उन्होंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण की और खनन एवं भूतत्व विभाग में चयनित हुए। देहरादून मुख्यालय में प्रशिक्षण के बाद उन्हें फील्ड ट्रेनिंग दी गई, जिसके पश्चात 2009 में उन्हें नैनीताल जिले में जिला खान अधिकारी का पद सौंपा गया। यह उनकी करियर की पहली पोस्टिंग थी, जहां से उनके असाधारण योगदान की शुरुआत हुई।

पहली बार नैनीताल से 165 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ

नैनीताल में जिला खान अधिकारी के रूप में राजपाल लेघा ने खनन क्षेत्र को व्यवस्थित करने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए। उन्होंने खनन से जुड़े कारोबारियों, जैसे माध्यम कारोबारी, स्टॉकिस्ट, स्टोन क्रशर एसोसिएशन और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया। स्थानीय स्तर पर गौला नदी से उपखनिजों की मात्रा बढ़ाने में उनका सहयोग सराहनीय रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि स्थानीय लोगों को मकान निर्माण और विकास कार्यों के लिए सस्ते दामों पर रेत-बजरी उपलब्ध होने लगी। साथ ही, उत्तराखंड सरकार को पहली बार खनन विभाग से सिर्फ जनपद नैनीताल से ही 165 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो उस समय तक का सबसे बड़ा राजस्व था।

मेहनत का फल उन्हें जल्द ही मिला। कांग्रेस सरकार के दौरान वर्ष 2013 में उन्हें उपनिदेशक खनन के पद पर पहली पदोन्नति प्राप्त हुई। इसके बाद उन्हें विभिन्न जिलों की जिम्मेदारियां सौंपी गईं, जहां उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया।

उदाहरण के लिए, उधम सिंह नगर जिले में उन्होंने 74 करोड़ रुपये, चंपावत में 37 करोड़ रुपये, पिथौरागढ़ में 38 करोड़ रुपये, तथा बागेश्वर और अल्मोड़ा में अभूतपूर्व राजस्व अर्जित करवाया। इन जिलों में उनकी पोस्टिंग के दौरान खनन प्रक्रिया को पारदर्शी और कुशल बनाया गया। उधम सिंह नगर में जहां औद्योगिक गतिविधियां अधिक हैं, उन्होंने स्थानीय उद्योगों के साथ मिलकर खनन सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की, साथ ही पर्यावरण नियमों का कड़ाई से पालन करवाया। चंपावत और पिथौरागढ़ जैसे सीमावर्ती जिलों में, जहां भौगोलिक चुनौतियां अधिक हैं, उन्होंने स्थानीय समुदायों को शामिल कर खनन को सतत विकास से जोड़ा। बागेश्वर और अल्मोड़ा में उनके प्रयासों से न केवल राजस्व बढ़ा, बल्कि नदियों और जंगलों का संरक्षण भी सुनिश्चित हुआ। इन जिलों में राजपाल लेखा ने खनन पट्टों की निगरानी को मजबूत किया, जिससे अवैध गतिविधियां न्यूनतम स्तर पर आईं।

खनन नीति 2023 तैयार की

वर्ष 2021 में लेघा को संयुक्त निदेशक कुमाऊं के पद पर तैनात किया गया। यहां से उनके करियर में तेजी

आई। उनके काम के बल पर वर्ष 2022 में उन्हें अपर निदेशक, देहरादून के पद पर पदोन्नत किया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने खनन पट्टों, समतलीकरण, रिवर ड्रेजिंग और गौला, कोसी तथा नंधौर नदियों में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित खनन नीति 2023 तैयार की। इस नीति के परिणामस्वरूप राज्य का राजस्व 646 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। उन्होंने हमेशा पर्यावरण और नदियों के अनुचित दोहन पर रोक लगाने को प्राथमिकता दी। उन्होंने अवैध खनन कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई की, कई वाहनों को जब्त किया और क्रशरों से अवैध उपखनिज की निकासी बंद करवाई। विभाग की ई-रवन्ना प्रणाली का दुरुपयोग रोकने के लिए शत-प्रतिशत प्रयास किए गए। प्रत्येक जिले में खनन निकासी रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिनकी मॉनिटरिंग देहरादून से की जाती है। इन कदमों से अवैध खनन पर प्रभावी लगाम लगी और पारदर्शिता बढ़ी।

खनन सुधारों में उत्तराखंड सरकार ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसीलिए केंद्र सरकार उत्तराखंड को 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि से पुरस्कृत किया है।

ई-टेंडरिंग प्रक्रिया को मजबूत किया

1 मई 2024 को सरकार ने लेघा को प्रभारी निदेशक बनाया, और 1 जुलाई 2024 को उन्होंने पूर्ण रूप से खनन निदेशक की जिम्मेदारी ग्रहण की। इस पद पर आते ही उन्होंने विभाग को नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया को मजबूत किया गया, मिनरल ट्रांसपोर्ट की डिजिटल सर्विलांस सिस्टम मॉनिटरिंग (ई-रवन्ना पोर्टल) को लागू किया गया, ई चेक गेट्स स्थापित किए गए और अवैध खनन रोकने के लिए तकनीकी प्लेटफॉर्म विकसित किए गए। इन प्रयासों का परिणाम वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1100 करोड़ रुपये के राजस्व के रूप में सामने आया। यह न केवल उत्तराखंड के लिए रिकॉर्ड है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर माइनिंग एक्सीलेंस के लिए राज्य को पुरस्कृत भी किया गया। उनके नेतृत्व में खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन और लगातार सुधारों के चलते उत्तराखंड को केंद्र सरकार से बड़ी प्रोत्साहन राशि हासिल करने में सफल रहा है। केंद्र के खान मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 की विशेष सहायता योजना के तहत उत्तराखंड को माइनर मिनरल्स रिफॉर्म्स में माह नवंबर 2025 में 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। इससे पहले भी माह अक्टूबर 2025 मैं राज्य को एसएमआरआई रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त होने पर 100 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है। इस प्रकार खनन क्षेत्र में उत्कृष्ट सुधारों और बेहतर नीतियों की बदौलत उत्तराखंड को कुल 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो चुकी है। उनका लक्ष्य 2025-26 में इस राजस्व को बनाए रखना और 2026-27 में 1300-1400 करोड़ तक पहुंचाना है। वे कहते हैं कि खनन को आर्थिक विकास का माध्यम बनाना चाहिए, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में राजपाल लेघा की पोस्टिंग्स ने राज्य के खनन क्षेत्र को समग्र रूप से मजबूत किया। नैनीताल में शुरू हुई उनकी यात्रा ने उन्हें उधम सिंह नगर जैसे औद्योगिक जिलों में ले जाकर विकास कार्यों को गति दी, जहां उन्होंने स्थानीय उद्योगों को सस्ती सामग्री उपलब्ध करवाई। चंपावत और पिथौरागढ़ में उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों की चुनौतियों का सामना किया और राजस्व को दोगुना किया। बागेश्वर और अल्मोड़ा में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में खनन को संतुलित रखा। अपर निदेशक के रूप में देहरादून में उन्होंने नीतिगत स्तर पर बदलाव किए, जैसे रिवर ड्रेजिंग को पर्यावरण अनुकूल बनाना। वर्ष 2023 में अपर निदेशक के रूप में उन्होंने कई स्टोन क्रशरों को नियम उल्लंघन के लिए सील किया, जो अवैध खनन पर सख्ती का उदाहरण है।

डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया

राजपाल लेघा की उपलब्धियां केवल राजस्व तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने विभाग में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया, जिससे पारदर्शिता बढ़ी और भ्रष्टाचार कम हुआ। उनकी खनन नीति 2023 अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसे अपनाया और अब जम्मू-कश्मीर भी इसे लागू करने की तैयारी में है। यह नीति पर्यावरण संरक्षण, सतत खनन और राजस्व वृद्धि का संतुलित मॉडल है। उनका मानना है कि खनन राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार है, लेकिन इसे स्थानीय समुदायों के हित में चलाना चाहिए। उनके प्रयासों से उत्तराखंड अब माइनिंग में अग्रणी राज्य बन रहा है, जहां रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास एक साथ चल रहे हैं।

उनके योगदान से उत्तराखंड ने न केवल राजस्व के नए कीर्तिमान स्थापित किए, बल्कि खनन को एक जिम्मेदार उद्योग बनाया। भविष्य में उनके टारगेट 1300-1400 करोड़ राजस्व के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेंगे। लेघा जी जैसे अधिकारी साबित करते हैं कि नवाचार और मेहनत से कोई भी क्षेत्र क्रांति ला सकता है।•